ratories in Delhi for testing the cases of adulteration in foodstuffs;

(b) the number of inspectors for detecting the cases of food adulteration; and

(c) the number of samples taken during the year 1963-64 and upto 30th September, 1964; and how many of them were found adulterated?]

स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० एस० नस्कर) : (क) इस कार्य के लिये दिल्ली नगर निगम की एक प्रयोगशाला है । इस दशा में कोई गैर-सरकारी प्रयोगशाला है या नहीं, सरकार को मालूम नहीं है ।

(ख) ३५ ।

(ग) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड के खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिये गये १०,०८२ नमूनों में से १,९८४ नमूने मिलावट वाले पाये गये ।

t[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OP HEALTH (SHRI P. S. NASKAR): (a) The Delhi Municipal Corporation maintains one laboratory for this purpose. Government is *iot aware of any private effort in this direction.

(b) Thirty-five.

(c) Out of 10,082 samples taken by food inspectors of the Delhi Municipal Corporation, the New Delhi Municipal Committee and the Delhi Cantt. Board, 1,984 were found adulterated.]

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या यह बतलाने की कृपा करेंगी कि जो मिलावट करने वाले लोग पाये गये, उनमें से कितनों के खिलाफ न्यायालय में चालान किया गया ?

DR. SUSHILA NAYAR: Madam, out of these cases for 1963 and 1964, prosecutions were launched in 1963 in respect of 1,017 cases, and 164 till 31st August 1964, and convictions came to 1522 in 1963 and 298 in 1964.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या यह बतलाने का कष्ट करेंगी कि यह ज्ञात है अथवा नहीं कि दिल्ली शहर में मिलावट की खाद्यान्न की सामग्री इतनी अधिक मात्रा में विक्रय की जा रही है कि उसकी सब लोग अनुभूति करते हैं ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति हमारे इंस्पेक्टर्स की संख्या की कमी की वजह से है या उनके द्वारा ठीक तरह से कार्य न करने की वजह से है या किन कारणों से है, इसके बारे में शासन क्या सोच रहा है ?

डा० सुशीला नायर : मैडम, इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं, तभी तो इतने लोगों को सजा हुई, इतने नमूने लिये गये और सारी कार्यवाही की गई । इसकी रोकथाम करने के लिये पूरी कोशिश हो रही है ।

नर्मदा सागर योजना

*३३८. **पंडित भवानी प्रसाद तिवारी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा सागर योजना का विवरण शीघ्र अनुमोदनार्थ उनके मंत्रालय को प्रेषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय लेने की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है ?

-|-|NARBADA SAGAR PLAN

*338. PANDIT BHAWANIPRASAD TIWARY: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Narbada Sagar Plan in the detailed

t[ ] English translation.

iorm has been submitted to his Ministry by the Madhya Pradesh Government for an early approval; and

(b) if so, what progress has been made in arriving at a decision?]

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एस० डी० मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां । चूंकि खोसला समिति सम्पूर्ण घाटी की परियोजनाओं का पुनरावलोकन कर रही है, अगली कार्रवाई रिपोर्ट के मिलने पर ही की जा सकेगी । रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

" f[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI S. D. MISRA) : (a) and (■b) Yes, Madam. Since the projects of the entire valley are under review by the Khosla Committee, the report Is awaited before further action can be taken.]

DR. K. L. RAO: It is true that this is a very important project for the country and the

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : क्या यह बात सही है कि इस योजना से न केवल मध्य प्रदेश का, बल्कि सारे देश का लाभ होने वाला है, तो सरकार यह बताये कि इसकी स्वीकृति में क्या झंझट है ?

completion of this project will be of great benefit to the nation hut there are some points of difference which have to be resolved between the Governments of Madhya Pradesh and Gujarat wheh are the two parties. They have got to be sorted out before the project is undertaken.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् यह बतलायेंगे कि वे कौन से स्पेसिफिक प्वाइंट्स हैं, जिनके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों में मतभेद हो रहा है और उनको हल करवाने के लिये और दोनों स्टेट्स के झगड़े को निपटाने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या विशेष प्रयत्न कर रही है ?

†[ ] English translation.

DH. K. L. RAO; I am glad to say that the difference between the two Governments relates not to the allocation of water which would have been more difficult to solve but relates to the height of the Naogaon project in Gujarat and the Punsa project in Madhya Pradesh. In order to resolve these differences, a Committee under the Chairmanship of Dr. Khosla has been appointed. It is expected that the report of this Committee will be ready by January, 1965, when we hope we will be able to take up this project.

SHRI A. D. MANI I should like to know the procedure which is going to be adopted by Dr. Khosla in reaching a decision on the subject. Will the respective State Governments be allowed to state their case personally through their representatives and will the Union Government express its disinterasted opinion on this subject before Dr. Khosla comes to a decision?

DR. K. L. RAO: The State Governments are to explain their respective views on the various proposals that they have put forward and the members of the Committee will visit the site and then draw up their report.

IMPORT OP FOODGRAINS UNDER PL 480

*339. SHRI P. K. KUMARAN: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission have studied the effect of importing foodgrains under PL 480 on the economy of India;

(b) if so, what are the main conclusions arrived at; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, whether such a study will be undertaken and, if *o, when?